पूर्ववर्ती जांच को मिलनी चाहिए, वह इस संबंध में एप्लाई नहीं होती है, क्योंकि जो भूतपूर्व मंत्री या प्रधान मंत्री रह चुके हैं, उन के ऊपर तो हाउस में रोज आरोप लगते हैं। उन्होंने देश में एमर्जेन्सी लगाई इस पर जो सवाल उठाया गया क्या किसी ने नोटिस दिया था ?

MR. SPEAKER I am not deciding that point

डा० बलदेव प्रकाश आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं यही कहना चाहता हू कि जो पहले प्रधान मंत्री या मंत्री रह चुके हैं उन पर जो आरोप लगते हैं उस के बारे में आप का पहले से नोटिस देना आवश्यक नही है। वह तो केवल सरकार के अन्दर जो आफिसर्ज काम करते हैं उन के खिलाफ कोई एलीगेशन लगाना हो तो नोटिस की जरूरत होती है

MR SPEAKER I have not ruled that way uptill now

डा० बलदेव प्रकाश आप मेरी बात सुन लीजिए। आप ने उन को 10 मिनट दिये हैं मुझे दो मिनट भी देने को तैयार नही है। उन्होने हर बात दस बार रिपीट की है, लेकिन मै रेपीटिशन नही कर रहा हू।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हू कि शिमला समझौते के वक्त अखबारो के द्वारा सारी जनता को पता है कि बातचीत टूट गई थी, बातचीत टूटने के बाद भूतपूर्व प्रधान मंत्री और श्री भुट्टो रात को मिले तो अगर कोई गुप्त बात नही हुई थी तो वे किस लिए मिले थे —यह हाउस के सामने बतलाया जाय। मिलने के बाद क्या फैसला हुआ—यह बात किसी के सामने नही आई, लेकिन यकदम संधि पर दस्तखत किये गये, इस का मतलब है कि कुछ न कुछ तो फैसला हुआ होगा। अखबारो में छप चुका था कि बातचीत टूट गई, उस के बाद रात को दो बजे मुलाकात हुई और यकदम सुबह दस्तखत हो गये—इस

लिए यह पता लगना चाहिए कि वहां पर क्या बात हुई थी और उस समझौते के मुताबिक जो बातें हुई थी, वे स्पष्ट होनी चाहिए।

MR SPEAKER, Now, matters under Rule 377—Shri Tarun Gogoi.

13.24 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

MATTERS UNDER RULE 377

(i) REPORTED DECISION OF O N G C TO SLOW DOWN CRUDE PRODUCTION IN NORTH-EASTERN REGION

SHRI TARUN GOGOI (Jorhat) By giving notice under Rule 377 I would like to draw the attention of the Minister of Petroleum and Chemicals to the reported decision of the Oil and Natural Gas Commission to slow down the crude production in the North-Eastrn Region, particularly, in Assam It has been a matter of great concern not only for the people of that region but to the whole nation to see this retrograde step of stepping down the production of crude oil when there are great prospects of increasing such production because of numerous deposits of oil reserves in Assam Nagaland and Tripura

Besides, it raises an apprehension in the minds of the people of that region that the Centre is not interested in the development of that area by continuing its policy of neglect and apathy towards this region While there is a great need to speed-up the crude production in order to move towards attaining self-sufficiency and all out efforts are being made to increase the production on the Bombay High, the slackening of such efforts in the North-Eastern region runs counter to the declared national policy on oil and the policy of removal of regional imbalances It has been reported that due to the limited capacity of the existing refineries and the limited capacity of the pipelines such steps are

[Shri Tarun Gogoi]

taken. If so, O.N.G.C. are to be blamed squarely for not taking adequate steps before, inspite of its knowledge of known deposits of crude in that region.

This is not the first time that such a thing has happened earlier also in Assam the oil field of Naharkatia though was discovered in the year 1952, the wells were kept sealed till 1962 when the Gauhati Refineries came up To avoid such complications in future, immediate steps should be taken and production in that region need not be stopped or slowed down by setting up a new refinery nearby the site of the reserves to meet all the requirements and thereby helping these backward regions to come up in the map of Petro-Chemical Industry in the country

(ii) REPORTED DIFFICULTIES FACED BY RAJKOT DIESEL OIL ENGINEERING INDUSTRY.

श्री धर्मसिंह भाई पटेल (पोरबन्दर) उपाध्यक्ष महोदय, लोक सभा के नियम 377 के अधीन लोक महत्व के निम्न वर्णित विषय 'गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश के राजकोट में बनते हुए डीजल आयल इजनों" की क्वालिटी (क्यू) मार्क की मान्यता (रिकगनीशन) उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश भूमि विकास बैंक की ओर से तारीख 1-4-78 से रद्द करने से राजकोट डीजल इंजीनियरिंग उद्योग पर बड़ा खतरा होने के बारे में मैं संक्षिप्त में वक्तव्य देना चाहता हूं।

गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश के राजकोट शहर में आयल इंजीनियरिंग के उद्योग का विकास हुआ है। इस उद्योग में डीजल क्रुड आयल इजन और इन के पुर्जे (स्पेयर पार्ट्स) बनाये जाते हैं। राजकोट में 160 डीजल आयल इजन उत्पादन करने की छोटी छोटी फैक्टरिया और डीजल इंजन के पुर्जे बनाने की करीब 2000 छोटी छोटी फैक्टरिया हैं।

राजकोट में वार्षिक करीब एक लाख डीजल इंजन बनते हैं जिनकी कीमत करीब 20 करोड रुपये के होती है। इन में 20,000 मजदूर काम करते हैं। समूचे देश में 3 लाख आयल इजन का उत्पादन होता है। इन में से राजकोट में एक लाख डीजल इजनो का वार्षिक उत्पादन होता है। इसी तरह से देश के एक तिहाई हिस्सा का उत्पादन सिर्फ राजकोट (सौराष्ट्र) में होता है।

राजकोट में वार्षिक उत्पन्न हुए इस एक लाख डीजल इजनो में से करीब 30 हजार डीजल आयल इजनो की उत्तर प्रदेश में बिक्री होती है और 20 000 इंजन मध्य पूर्व और दूर पूर्व के दूसरे देशो में निर्यात होते हैं और बकाया देश के अन्दर राज्यों में बिक जाते है।

इन डीजल आयल इजनो की गुणवत्ता के लिए इण्डियन स्टैण्डर्ड इस्टीट्यूशन से राजकोट के 16 बडे उत्पादको ने आई एस आई के मार्क लिए है। आई एस आई मार्क लेने के लिए करीब एक लाख रुपय की मशीनरी लगानी पडती है। यह छोटे उद्योग वाले नही कर सकते है। इसलिए गुजरात और अन्य सरकारो ने आई एस आई जैसे 'क्यू' मार्क की पद्धति अपनाई है। इनमें केवल छोटे उद्योग वालो को 20 हजार रुपये का खर्चा करना पडता है। और गुजरात में ऐसी यूनिटो के क्य मार्क के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन किये गये है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने और उत्तर प्रदेश भूमि विकास बैंक ने राजकोट में बनते हुए यह क्यू मार्क वाले डीजल इजनो की मान्यता ता० 1-4-78 से बद कर दी है। इससे राजकोट के करीब 7,000 मजदूरो और छोटी फैक्ट्री वालो को कठिनाइया उत्पन्न हुई हैं।

राजकोट इंजीनियरिंग एसोसिएशन राजकोट ने ता० 22-3-78 से तार से भारत